और संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति के प्रतिनिधियों के रूप में नामित किया गया है। दोनों पक्षों की ओर से अधिकारियों के सुगठित दल ने दोनों नेताओं की सहायता की थी।

यह बातचीत पूर्णाधिवेशनों और नामित अधिकारियों के छोटे-छोटे समूहों में तीन दिन से अधिक तक चली। इसके अतिरिक्त श्री स्ट्रोब तालबोट ने प्रधान मंत्री, रक्षा मंत्री और कुछ राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ मुलाकात भी की।

बातचीत उन व्यापक प्रस्तावों के आधार पर चलाई जा रही है जिन्हें भारत ने निरस्त्रीकरण तथा शस्त्र अप्रसार मामलों, यथा - विस्फोटक नाभिकीय परीक्षणों पर एक-पक्षीय छूट, इसे विधितः दायित्व में बदलने पर बातचीत करने की इच्छा, एफ एम सी टी पर रचनात्मक बातचीत में सम्मिलित होने के निर्णय और संवेदनशील प्रौद्योगिकियों के निर्यात पर कड़े नियंत्रण — पर हमारी नीतियों की पुनः पुष्टि करने पर प्रस्तुत किया था।

अमरीका के साथ बातचीत के कई दौर के बाद बातचीत का दायरा संकुचित हुआ है और अब यह सुरक्षा, निरस्त्रीकरण और शस्त्र अप्रसार यथा-नाभिकीय परीक्षण प्रतिबंध संधि, भारतीय सुरक्षात्मक स्थिति और निर्यात नियंत्रण मुद्दे से जुड़ चार मुद्दों पर केन्द्रित है।

दोनों देशों के शिष्टमंडलों ने बातचीत के निष्कर्ष पर सन्तोष व्यक्त किया। पिछली बातचीतों की तरह दोनों पक्षों के सुरक्षा संबंधी पर परिप्रेक्ष्यों को और स्पष्ट किया गया ताकि अपने-अपने परिप्रेक्ष्यों में मेल-मिलाप की स्थिति बनाई जा सके।

यह निर्णय किया गया है कि निर्यात नियंत्रण पर अनुवर्ती बातचीत के लिए भारत-अमरीकी विशेषज्ञ स्तर के दलों की मार्च में एक बैठक होगी। शिष्टमंडलों के नेता भी परस्पर सम्पर्क में रहेंगे। इन बातचीतों के चलते दोनों पक्ष अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए रचनात्मक वातावरण बनाने का प्रयास करेंगे।

(ख) और (ग) बातचीत सुरक्षा, निरस्त्रीकरण और अप्रसार से संबंधित मुद्दों पर केन्द्रित है। इस बात पर सहमति हुई कि क्षेत्रीय मसलों को साथ-साथ अलग से रखा जाएगा। तथापि, अफगानिस्तान सहित अन्य अलग-अलग चर्चाओं के लिए दोनों पक्षों के संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति का लाभ उठाया जाता है।

अमरीका ने यह बताया है कि उसका यह विचार है कि अफगानिस्तान में सैन्य समाधान सम्भव नहीं है। और वह अफगानिस्तान में व्यापक आधारित सरकार की दिशा में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान के अन्तर्गत आपसी बातचीत से हुए समझौते के पक्ष में है।

'संयुक्त राष्ट्र संघ की छः योग दो प्रक्रिया (सिक्स प्लस टू प्रोसेस)

378. **डा० महेश चन्द्र शर्मा:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ की 'छः योग दो प्रक्रिया' (सिक्स प्लस टू प्रोसेस) क्या है; और

(ख) यह भारतीय प्रायद्वीप से किस प्रकार जुड़ा है?

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह): (क) और (ख) "सिक्स प्लस टू प्रोसेस" से अभिप्राय अनौपचारिक परामर्श की उस प्रक्रिया से है जिसके अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र के कुछ सदस्य राज्य अफगानिस्तान के मसले पर एक-दूसरे से परामर्श करते हैं। इसमें ईरान, पाकिस्तान, उजबेकिस्तान, ताजिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, चीन रूसी परिसंघ तथा अमरीका शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र में इस दल की कोई औपचारिक उपस्थिति नहीं है। यह अनौपचारिक दल भारतीय प्रायद्वीप से सीधे तौर पर संबद्ध नहीं है।

जम्मू और कश्मीर का पाकिस्तानी मानचित्र में गलत तरीके से दर्शाया जाना

379. **श्री डी०पी० यादव:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर के एक हिस्से को अपने मानचित्र में दर्शा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में अपनी आपत्ति दर्ज कराई है; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह): (क) से (ग) पाकिस्तान अपने मानचित्रों में जम्मू और कश्मीर के भारतीय राज्य की स्थिति को सही नहीं दर्शाता है। इस मुद्दे पर सरकार के विचारों की पाकिस्तान को पूरी जानकारी है।